ऊर्जा प्रबंधन और सौर क्रांति से बिजली दरें रहीं स्थिर

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां लगातार छह वर्षों से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ता को मिल रहा है क्योंकि घरेलू बजट पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा। सरकार और बिजली वितरण कंपनियों के बेहतर प्रबंधन का नतीजा है कि कुछ ही वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला। इसकी वजह बिजली चोरी पर सख्ती, तकनीक आधारित बिलिंग, लाइन लास में कमी, समय पर मरम्मत और बड़े स्तर पर किए गए सुधार हैं।

प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने से भी बिजली की

- प्रदेश बना ऊर्जा प्रबंधन का राष्ट्रीय माडल, सौर ऊर्जा ने बढ़ाई रोशनी और रोजगार

लागत नियंत्रण में रही। शहरों और गांवों में ओवरलोडिंग कम करने, भूमिगत केबलिंग, पुराने तारों और ट्रांसफार्मरों को बदलने जैसे कामों से बिजली व्यवस्था और विश्वसनीय बनी है। स्मार्ट मीटर लगाने और ऊर्जा बचत अभियानों से राजस्व बढ़ा और प्रणाली पारदर्शी हुई।

बिजली दरें स्थिर रहने से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि उद्योगों की लागत भी नियंत्रित रही है। निवेशक स्थिर ऊर्जा कीमतों वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए यूपी तेजी से एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य बन रहा है। विभाग का कहना है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश ने नए रिकार्ड बनाए हैं। रूफटाप सोलर और ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट्स की तेज गति से स्थापना के चलते राज्य अब महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। 18 महीनों में 2,81,769 रूफटाप सोलर सिस्टम लगाए गए, जबकि सिर्फ 4.5 महीनों में ही 1,30,000 नई इकाइयां स्थापित हुईं। सौर क्रांति से प्रदेश में अब तक 54,000 से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिला है। वहीं सोलर माड्यूल, इन्वर्टर, वायरिंग, इंस्टालेशन और लाजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में देशभर में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं।